नव भारत
| संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी | प्रेरणा स्त्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी |

एथेनॉल ; सभी शंकाओं का समाधान करे सरकार

पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण भारत की ऊर्जा नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. सरकार ने वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण (ई-20) का लक्ष्य हासिल करने का दावा किया है. संसद में भी सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यापक वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ही इस नीति को लागू किया गया है और अब तक ई-20 के कारण इंजनों को किसी प्रकार के नुकसान का प्रमाण नहीं मिला है. फिर भी देश के एक बड़े वर्ग में एथेनॉल को लेकर अनेक आशंकाएं बनी हुई हैं. सरकार का दायित्व केवल नीति बनाना नहीं, बल्कि उससे जुड़े हर संदेह का तथ्यात्मक और पारदर्शी समाधान भी करना है.

सबसे बड़ी चिंता वाहन मालिकों की है. जिन लोगों के पास पुराने मॉडल की गाड़ियां हैं, वे यह जानना चाहते हैं कि ई-20 ईंधन उनके इंजन, माइलेज और रखरखाव पर क्या प्रभाव डालेगा. सोमवार को संसद में सरकार ने स्वीकार किया कि ई-20 समर्थित वाहनों की सटीक संख्या का अनुमान उपलब्ध नहीं है, लेकिन परीक्षणों के आधार पर इंजन को किसी गंभीर नुकसान से इनकार किया गया है. यदि कुछ परिस्थितियों में माइलेज में मामूली कमी आ सकती है, तो सरकार को यह बात भी स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए. आधी-अधूरी जानकारी ही अफवाहों और भ्रम को जन्म देती है.

एथेनॉल नीति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू कृषि से जुड़ा है. एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने, मक्का तथा अन्य कृषि उत्पादों से होता है. इससे किसानों को अपनी उपज का अतिरिक्त बाजार मिलता है, चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सकती है. विशेष रूप से मक्का उत्पादन बढ़ाने वाले राज्यों के किसानों के लिए यह आय बढ़ाने का अवसर बन सकता है. लेकिन इसके साथ कुछ गंभीर प्रश्न भी जुड़े हैं. यदि एथेनॉल उत्पादन के लिए खाद्यान्न फसलों का अत्यधिक उपयोग होने लगे, तो खाद्य सुरक्षा, फसल विविधता और जल संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है. गन्ना पहले से ही अत्यधिक पानी की मांग वाली फसल है. ऐसे में यह स्पष्ट होना चाहिए कि एथेनॉल नीति खाद्यान्न उत्पादन और पर्यावरणीय संतुलन की कीमत पर आगे नहीं बढ़ेगी. सरकार को यह भी बताना चाहिए कि भविष्य में कृषि अवशेषों, दूसरी पीढ़ी (2जी) के एथेनॉल तथा गैर-खाद्य जैव संसाधनों को कितना महत्व दिया जाएगा.

मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में एथेनॉल संयंत्रों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और सरकार इनके लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन भी दे रही है. यह निवेश रोजगार, उद्योग और ग्रामीण विकास के लिए सकारात्मक हो सकता है, लेकिन इसके आर्थिक, पर्यावरणीय और कृषि संबंधी प्रभावों का नियमित सार्वजनिक मूल्यांकन भी उतना ही आवश्यक है.

भारत को आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करनी है, कार्बन उत्सर्जन घटाना है और किसानों की आय बढ़ानी है. एथेनॉल इन तीनों लक्ष्यों की दिशा में उपयोगी माध्यम बन सकता है. लेकिन किसी भी बड़ी नीति की सफलता केवल उसके उद्देश्यों से नहीं, बल्कि जनता के विश्वास से तय होती है. इसलिए अब समय आ गया है कि सरकार व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए, सभी वैज्ञानिक अध्ययन सार्वजनिक करे और वाहन मालिकों, किसानों तथा विशेषज्ञों के हर प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दे. एथेनॉल पर जितनी पारदर्शिता होगी, उतना ही इस महत्वाकांक्षी नीति को समाज का व्यापक समर्थन मिलेगा.

त्रिभाषा फॉर्मूला | बस्ते में तीन भाषाएं, कंधे पर एक बोझ

ओजस्कर पाण्डेय

> त्रिभाषा फ़ॉर्मूला अपने मूल स्वरूप में भारत की भाषाई विविधता को उसकी शक्ति में बदलने का प्रयास है. यह ऐसा विचार है जो विद्यार्थियों को अपनी जड़ों से भी जोड़ता है और दुनिया से भी. किंतु किसी भी महान विचार की तरह इसकी सफलता भी क्रियान्वयन की ईमानदारी, संसाधनों की उपलब्धता और राजनीतिक परिपक्वता पर निर्भर करेगी. यदि इसे संवाद, लचीलेपन और समान अवसर की भावना के साथ लागू किया गया, तो यह भारत की ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक एकता का मजबूत आधार बन सकता है. परंतु यदि इसे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, भाषाई वर्चस्व या अधूरी तैयारियों के साथ लागू किया गया, तो समृद्धि का यह सपना उलझनों के जाल में फँस सकता है. भाषा का भविष्य किसी एक भाषा की जीत में नहीं, बल्कि भारत की सभी भाषाओं के सम्मान, सह-अस्तित्व और समान अवसर में निहित है. यही त्रिभाषा फ़ॉर्मूले की वास्तविक कसौटी भी है.

भाषा केवल अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि अवसर, अस्मिता और राष्ट्रीय एकता का आधार भी है। इसलिए भाषा नीति का मूल्यांकन भावनाओं से नहीं, दूरदृष्टि और व्यावहारिकता से किया जाना चाहिए.

भारत में भाषा का प्रश्न जितना शैक्षिक है, उतना ही राजनीतिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक भी. यही कारण है कि जब भी त्रिभाषा फ़ॉर्मूले की चर्चा होती है, बहस केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहती; वह संघवाद, सांस्कृतिक पहचान, क्षेत्रीय स्वायत्तता और समान अवसर जैसे व्यापक प्रश्नों को भी अपने साथ लेकर चलती है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने एक बार फिर इस फ़ॉर्मूले को नई ऊर्जा देने का प्रयास किया है. इसका उद्देश्य स्पष्ट है—विद्यार्थियों को बहुभाषी बनाना, भारतीय भाषाओं का संरक्षण करना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए उन्हें सक्षम बनाना. परंतु प्रश्न यह है कि क्या यह नीति अपनी मंशा के अनुरूप परिणाम दे पाएगी, या फिर भारत की जटिल भाषाई वास्तविकताओं में उलझकर रह जाएगी? भारत विश्व का सबसे बड़ा भाषाई लोकतंत्र है. यहाँ सैकड़ों भाषाएँ और हजारों बोलियाँ जीवंत हैं. संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि अनेक भाषाएँ आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं. ऐसी विविधता किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक शक्ति हो सकती है, किंतु शिक्षा व्यवस्था के लिए यह एक जटिल प्रशासनिक चुनौती भी है. त्रिभाषा फ़ॉर्मूला इसी चुनौती का समाधान खोजने का प्रयास था, जिसकी परिकल्पना 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई और बाद में 1986 तथा 2020 की शिक्षा नीतियों में भी इसे स्थान मिला.

इस नीति की मूल भावना अत्यंत सकारात्मक है. मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा से बच्चों की सीखने की क्षमता बेहतर होती है, दूसरी भारतीय भाषा उन्हें देश की विविध संस्कृति से जोड़ती है और अंग्रेज़ी उन्हें वैश्विक ज्ञान, विज्ञान तथा रोजगार के अवसरों तक पहुँच प्रदान करती है. शिक्षा मनोविज्ञान और यूनेस्को सहित अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने का समर्थन किया है. इस दृष्टि से देखा जाए तो त्रिभाषा फ़ॉर्मूला भारत को बहुभाषी और ज्ञान-आधारित समाज बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल प्रतीत होता है किन्तु किसी भी नीति की सफलता उसकी अवधारणा से नहीं, बल्कि उसके क्रियान्वयन से तय होती है. यहीं से त्रिभाषा फ़ॉर्मूले की वास्तविक परीक्षा प्रारंभ होती है. देश के अनेक सरकारी विद्यालय आज भी पर्याप्त शिक्षकों, पुस्तकालयों और बुनियादी संसाधनों के अभाव से जूझ रहे हैं. एकल शिक्षक विद्यालयों की संख्या अभी भी चिंताजनक है. ऐसे में तीन भाषाओं के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता एक गंभीर प्रश्न है. यदि भाषा पढ़ाने वाला शिक्षक ही उपलब्ध न हो तो नीति केवल सरकारी दस्तावेज़ों तक सीमित रह जाती है. दूसरी बड़ी चुनौती भारत की भाषाई राजनीति है. दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु, लंबे समय से दो-भाषा नीति का समर्थक रहा है. वहाँ हिंदी को अनिवार्य बनाए जाने की किसी भी संभावना को सांस्कृतिक स्वायत्तता पर हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है. पूर्वोत्तर भारत के अनेक राज्यों में भी स्थानीय भाषाओं के संरक्षण को लेकर संवेदनशीलता है. इसलिए त्रिभाषा फ़ॉर्मूला कई बार राष्ट्रीय एकीकरण के बजाय भाषाई वर्चस्व की बहस में बदल जाता है. यह स्थिति बताती है कि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि पहचान और आत्मसम्मान का प्रश्न भी है. विडंबना यह भी है कि जिस नीति का उद्देश्य समान अवसर देना है, वही कई बार असमानता को बढ़ाने का कारण बन जाती है. महानगरों के निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास प्रशिक्षित शिक्षक, डिजिटल संसाधन और आधुनिक भाषा प्रयोगशालाएँ उपलब्ध हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा तक नहीं मिल पाती. परिणामस्वरूप बहुभाषी शिक्षा का लाभ समाज के संपन्न वर्ग तक सीमित रह जाता है, जबकि वंचित वर्ग अतिरिक्त शैक्षणिक बोझ का सामना करता है. त्रिभाषा फ़ॉर्मूले की सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती अंग्रेज़ी की भूमिका को लेकर भी सामने आती है. आज वैश्विक अर्थव्यवस्था, उच्च शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, न्यायपालिका और कॉर्पोरेट क्षेत्र में अंग्रेज़ी का प्रभाव निर्विवाद है.

दिल्ली डायरी

सीजेपी की रणनीति बनी छात्र इकाइयों के लिए सबक

प्रवेश कुमार मिश्र

नीट पेपर लीक घोटाले को लेकर काकरोच जनता पार्टी के भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद बैकफुट पर आई केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए जाने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जल्दबाजी में छात्रों के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश जारी किए जाने के बाद इस आंदोलन को जिस तरह सफलतम आंदोलन की श्रेणी में रखकर चर्चा हो रही है, उसके बाद भाजपा व कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के छात्र इकाईयों के रणनीतिकारों के होश उड़ गए हैं.

चर्चा है कि बड़े व स्थापित दलों के शीर्ष नेतृत्व ने अपने छात्र इकाई के वरिष्ठ नेताओं को सीजेपी की रणनीति को बारीकी से अध्ययन करने को कहा गया है. क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से बगैर सांगठनिक ढांचे को पूरे देश के छात्रों को जोड़ा गया और उन्हें एकजुट कर आंदोलन को धार दी गई ,यह रणनीति विमर्श का विषय है. इतना ही नहीं बदलते दौर में जिस परिपक्वता के साथ सीजेपी के प्रवक्ताओं ने केन्द्रीय मंत्रियों से बातचीत कर उन्हें अपनी शर्तों पर झूकने को मजबूर किया उसकी चौतरफा सराहना हो रही है. कहा जा रहा है कि एबीवीपी व एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्षों ने अपनी ईकाईयों को नए सिरे से तैयार करने की रणनीति बनाई है.

बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा ने झोंकी ताकत

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा खाली की गई बांकीपुर विधानसभा सीट इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी है. एक विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से भाजपाई रणनीतिकार अपनी ताकत झोंक कर घर-घर जाकर भाजपाई उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं उससे साफ है कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर द्वारा एक उम्मीदवार के रूप में दी गई चुनौती भाजपाई रणनीतिकारों के लिए भारी पड़ रही है.

संसद के मानसून सत्र में मौजूद बिहार के भाजपाई सांसद जिस घबराहट व बेचैनी के साथ बांकीपुर उपचुनाव की चर्चा करते हुए आम मतदाताओं के रूख के बारे में बता रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा का गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र में भी लड़ाई एकतरफा नहीं है. बताया जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा ज्यादातर सांसदों, लगभग सभी विधायकों, जिलाध्यक्षों, पूर्व सांसदों व विधायकों को गली गली में घुमकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाना सब कुछ समझने के लिए काफी है. चर्चा यह भी है कि कांग्रेसी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बढ़ते कदम पर नजर रखे हुए है.

विपक्षी एकता के साथ रखने का प्रयास

संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न संविधान संशोधन विधेयक और विधेयकों को पारित कराने के लिए सदन के अंदर जिस तरह से अंकगणित ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है उसके बीच विपक्षी एकजुटता को बनाए रखने की कोशिश भी की जा रही है. इंडिया गठबंधन अपने मौजूदा व पूर्व सहयोगियों को एकजुट करने का प्रयास आरंभ करते हुए डीएमके व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बहुस्तरीय विमर्श करते हुए सदन के अंदर एकजुटता बनाए रखने की कोशिश कर रही है.

शरद पवार के रुख पर है कांग्रेस की नजर

एनसीपी शरद गुट व अजीत पवार गुट की एकजुटता की सुगबुगाहट के बीच शरद पवार व सुप्रिया सुले की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है. बदलते राजनीतिक परिदृश्य में मेल-मिलाप के इस दौर को इंडिया गठबंधन के लिए बेहतर खबर नहीं मानी जा रही है. चर्चा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एनसीपी को शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के माध्यम से इंडिया गठबंधन में बने रहने के लिए प्रयास किया जा रहा है. इतना ही नहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे द्वारा भी महाराष्ट्र की रणनीति को लेकर एकजुटता बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है.

जलजीवन योजना की खामी पर कैग की आपत्ति

'हर घर जल' प्रमाणपत्र में त्रुटि की वजह से योजना की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग गया. रिपोर्ट के अनुसार गांव, जिला व राज्य स्तर पर नियोजन में अनेक प्रणालीगत त्रुटियां पाई गईं. बुनियादी सर्वेक्षण नहीं किया गया था.

महाराष्ट्र की जलजीवन मिशन योजना को लागू करने में हुई गंभीर खामियों पर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) ने आपत्ति उठाई है. यह योजना 2019 से 2024 के बीच लागू की गई थी. इसमें अपर्याप्त नियोजन, भरोसेमंद जलस्रोत के बगैर योजना को मंजूरी, प्रक्रिया न किए गए पानी की आपूर्ति जैसी बातें सामने आईं. घरों में नल द्वारा पानी की सप्लाई नहीं होने पर भी 2026 की रिपोर्ट में कुछ गांवों में 'हर घर जल' का दावा किया गया. कैग ने पुणे, सोलापुर, ठाणे, अहिल्यानगर, जलगांव व कोल्हापुर जैसे 6 जिलों में जलजीवन योजना लागू किए जाने की जांच-पड़ताल की. उसमें स्वच्छता मिशन तथा लागू करने वाली संस्था के आंकड़ों में फर्क नजर आया. प्रॉपर्टी की जियो टैगिंग में पुनरावृत्ति तथा 'हर घर जल' प्रमाणपत्र में त्रुटि की वजह से योजना की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लग गया. रिपोर्ट के अनुसार गांव, जिला व राज्य स्तर पर नियोजन में अनेक प्रणालीगत त्रुटियां पाई गईं. बुनियादी सर्वेक्षण नहीं किया गया था. कृतियोजना में जलसुरक्षा, भरोसेमंद जलस्रोत, आर्थिक नियोजन व मानव बल का विवरण शामिल नहीं किया गया. जलस्रोत नहीं होने पर भी कुछ योजनाओं को मंजूरी दे दी गई. इसलिए प्रक्रिया रहित पानी की सप्लाई की गई. कुछ पात्र घरों का योजना में समावेश नहीं किया गया. निजी नल, अधूरे नियोजन, बार- बार किए गए बदलाव तथा अतिरिक्त काम की वजह से परियोजना के खर्च में लगभग 9,608.87 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई. इसके अलावा राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की पूर्वानुमति लिए बगैर कार्यादेश जारी किए गए. ठेकेदारों की बोली क्षमता का गलत मूल्यांकन किया गया. लेखा परीक्षण में यह भी दर्ज किया गया कि जलापूर्ति योजना का बीमा निकालते समय अनियमितता बरती गई. अतिरिक्त काम की डिपॉजिट राशि अधूरी स्वीकार कर ठेके की शर्तों का उल्लंघन किया गया. फिटनेस सर्टिफिकेट व ऑडिट की गई बैलेंसशीट दाखिल करने में विलंब की वजह से केंद्र व राज्य सरकार से मिलने वाली निधि के समय पर वितरण तथा उपयोग पर प्रतिकूल असर पड़ा व काम में विलंब हुआ.

निशानेबाज

मंत्री पर आई नई जिम्मेदारी बना एक और विभाग का प्रभारी

मंत्री को थका-हारा, परेशान और निढाल देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, 'आज आपका हसीन चेहरा इतना गमगीन क्यों नजर आ रहा है? कहीं आप पर भी इस्तीफा देने का भारी दबाव तो नहीं आ गया? कहो तो गजल सुना दूं- तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो!'

मंत्री ने कहा, 'माय डियर, तुम नहीं जानतीं कि हम पर काम का कितना बोझ है. पहले ही ढेर सारे विभागों की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर थी, अब उस इस्तीफा देने वाले मंत्री के विभाग का अतिरिक्त भार हमें सौंप दिया गया. वह बड़ा खतरनाक विभाग है. उसे संभालने वाला मंत्री सीधे युवाओं के निशाने पर आ जाता है. उसे डर लगता है कॉकरोच कहीं उसके नाक-कान में न घुस जाएं. सारे मंत्रिमंडल में मैं ही अकेला मिला, जिसे यह दायित्व सौंपा गया.'

पत्नी ने कहा, 'यह आपकी विशेष योग्यता का पुरस्कार है. प्रधानमंत्री ने आप पर भरोसा जताया है. इसके लिए पार्टी तो बनती ही है. मुस्कुराइए कि आप

दिल्ली में हैं.' मंत्री ने कहा, 'लोग आते हैं, लोग जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं! कंधे पर लदा बोझ हमारे घुटनों पर आएगा. ऐसे में कहीं हम लड़खड़ाकर गिर न जाएं! उम्र के साथ अस्थियां कमजोर होने लगती हैं. हमें डर है कि बोन डेंसिटी कम न हो जाए!'

पत्नी ने कहा, 'आप व्यर्थ ही परेशान हो रहे हैं. जब मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में गोल्ड की हैट्रिक लगाते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो क्या आप मर्द होकर भी एक अतिरिक्त मंत्रालय का भार नहीं उठा सकते?' मंत्री ने कहा, 'मीराबाई को राणा ने और प्रल्हाद को हिरण्यकश्यप ने जहर पिलवाया था. जैसे प्रल्हाद विष्णुभक्त था वैसे ही हम भी नमोभक्त हैं इसलिए हमें यह विवादास्पद पेपरलीक वाला विभाग किसी तरह संभालना ही पड़ेगा. हमें फिल्म 'मदर इंडिया' का गीत याद आ रहा है- दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा!'

पत्नी ने कहा, 'सारी परेशानी भूल जाइए. सरकार में सारा काम तो सीनियर आईएएस सेक्रेटरी संभालते हैं, मंत्री को सिर्फ फाइल पर साइन करना पड़ता है. इसलिए बोझ की चिंता मत कीजिए. प्रधानमंत्री को पत्र लिख दीजिए कि आपने हमें शिक्षा मंत्रालय का प्रभारी बनाया जिसके लिए हम आभारी हैं. जैसा जमेगा वैसी जिम्मेदारी निभाएंगे!'

संपादकीय बोर्ड | प्रबंध संपादक : सुमीत माहेश्वरी, समूह संपादक : क्रांति चतुर्वेदी

शब्द-सागर : डॉ. सागर खादीवाला

CROSS WORD 12333 - डॉ. सागर खादीवाला

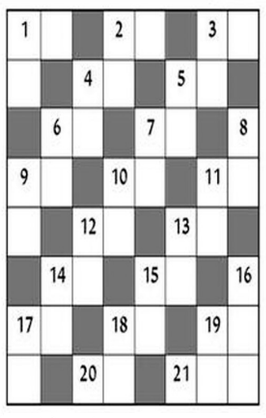

बाएं से दाएं

1. प्रसिद्ध, मशहूर (सं.) 2. वह अब एक बार और 3. डर 4. हावभाव, नखरा 5. करतल ध्वनि, चाबी 6. खीसा 7. एक घास 9. सफेद कुम्हडा 10 मर्तबा, दफा 11 परिमाण, नापतोल आदि 12 वीर-बहादुर, वह जो धर्म के लिए युद्ध करे 13. पिता, मरे हुए पूर्वज 14. स्वभाव की प्रवृत्ति, मिजाज, उत्तम स्वभाव या आचरण 15. कुर्सी-चौकी, मेज-पलंग आदि के नीचे लगे हुए छोटे खंबे जिनके सहारे इनका ढांचा खड़ा रहता है 17. तंतु, महीन सूत 18. शब्द का अभिप्राय, मतलब 19. अग्नि, जलन 20. संसार, जग 21. भागा हुआ

ऊपर से नीचे

1. विचार, एक विशेष गान पद्धति 2. किसी पर जान देने वाला, आसक्त 3. जो स्वभाव से अच्छी हो 4. इस समय, अभी 5. चमक, सामर्थ्य 6. वडा, अग्रज 7. फासले पर जो निकट न हो 8. अंत:करण की वह वृत्ति, जिससे संकल्प-विकल्प होता है, इच्छा, इरादा, विचार 9. वृक्ष 10. शर्त, दांव 11. माता 12. कपोल 13. पति, स्वामी 14. कांच, दर्पण, आईना 15. राजा, पृथ्वीपति, अर्जुन का एक नाम 16. समंदर 17. बालू 18. घोड़ा 19. लकड़ी चीरने का औजार

भु	र	का	ना	■	भ	न	क
जं	ग	ली	■	भ	र	स	क
ग	■	न	वा	ग	त	■	ड़ी
■	उ	■	स	त	■	आ	■
उ	ब	ल	ना	■	स	वा	री
प	ट	■	■	सु	हा	ग	■
वा	न	प्र	स्थ	■	इ	म	ली
स	■	भा	ल	ना	■	न	ग

ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष के प्रारंभ में व्यापारिक कार्यों में अधिक परिश्रम से आंशिक सफलता मिलेगी. व्यय और संतान की चिन्ता से मन अशांत रह सकता है, वाणी में कठोरता रहेगी. निर्णय सोच समझकर करना हितकर रहेगा. वर्ष के मध्य में सत्ता सुख से संतोष रहेगा. भाईयों का सहयोग बना रहेगा. वर्ष के अन्त में नवीन कार्यों में रूचि रहेगी. व्यापार में लाभ होगा.

मेष और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को मान सम्मान मिलेगा. वृष और तुला राशि के व्यक्तियों को परिश्रम अधिक करना होगा. कर्क राशि के व्यक्तियों को सत्ता पक्ष में रूचि रहेगी. सिंह राशि के व्यक्तियों को संतान की चिन्ता रहेगी. मिथुन और कन्या राशि के व्यक्तियों को स्वास्थ्य लाभ होगा, मकर और कुंभ राशि के व्यक्तियों को कार्य में वृद्धि होगी. धनु और मीन राशि के व्यक्तियों को सोच समझकर निर्णय लेना हितकर रहेगा.

आज जन्मे शिशु का भविष्य

आज जन्म लिया बालक सुन्दर, सुशील, होशियार होगा. सर्विस की ओर अधिक झुकाव रहेगा. कार्यकुशल तथा परिश्रमी होगा. मित्रों की संख्या सीमित रहेगी. जन्म स्थान से दूर रहकर अपनी उन्नति करेगा.

मेष- युवाओं को कैरियर में आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा. वाकपटुता पर नियंत्रण रखें. मित्रता उपयोगी रहेगी. परिश्रम अधिक करना होगा.

वृषभ- अपनी ताकत का इस्तेमाल विरोधियोंको रोकने में करना पड़ेगा. वाहनादि का सुख प्राप्त होगा. भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी. मित्रवर्ग आपकी मदद करेंगे.

मिथुन- व्यर्थ के झगड़े में आपका समय बर्बाद हो सकता है. मांगलिक खर्च संभव है. अतिथि वृषभमन होगा. हर्ष बना रहेगा. पूज्य व्यक्ति की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी.

कर्क- रूकी हुई योजनाओं में गति आयेगी. कार्य विस्तार की संभावना है. आत्म विश्वास एवं मनोबल बना रहेगा. इच्छितकार्यों की पूर्ति होगी.

सिंह- दूसरों की आलोचना से घबराकर कार्य योजना बीच में ही छोड़ सकते हैं. सोचे हुये कार्यों में सफलता के योग है. मित्रों एवं सहयोगियों का सहयोग प्राप्त होगा.

कन्या- आप बेहतर तरीके से काम निपटाने का प्रयास करेंगे. सहयोगी आपका विरोध कर सकते है. व्यापार व्यवसाय में लाभ सामान्य ही रहेगा.

तुला- थोडी परेशानी के बावजूद आपकी सफलता सुनिश्चित है, सामाजिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी. यश, मान सम्मान प्राप्त होगा.

वृश्चिक- मन में चल रही उलझन आपको फैसला लेने में रोकेगी. राजकीय कार्योंमें सफलता मिलेगी. लाभदायक योजना की रूपरेखा पर विचार विमर्शहोगा.

धनु- बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी चिन्ता रहेगी, जोखिम केकार्यों से दूर रहें. आवेश में लिया गया निर्णय नुकसानदायकरहेगा. व्यापारिक समस्याओं का समाधान होगा.

मकर- कड़ी मेहनत से शानदार परिणाम मिलेंगे, अनावश्यक टकराव छोड़कर काम पर ध्यान दें. किसी दूर गये मित्र के संबंध में शुभ समाचार मिलेगा.

कुम्भ- रूकी हुई योजना फिर से शुरू करने का मन बनेगा. पारिवारिक सुख तथा सौहार्द बना रहेगा. नवीन योजनाओं का शुभारंभ होगा.

मीन- नए कारोबार में निवेश की संभावना बनेगी. पारिवारिक मामले उलझने से चिन्ता होगी. अपव्यय पर नियंत्रण रखें. संपत्ति वाहनादि का सुख प्राप्त होगा.

उदयकालीन ग्रह चाल

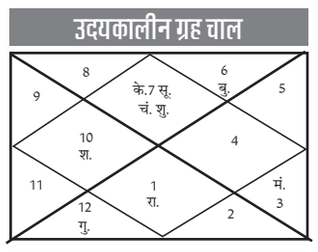

पंचांग

रा.मि. 07 संवत् 2083 आषाढ शुक्ल पूर्णिमा बुधवासरे रात 7/26, उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे दिन 4/11, प्रीति योगे रात 1/21, विष्टि करणे सू.उ. 5/23, सू.अ. 6/37, चन्द्रचार मकर, पर्व- स्नानदान व्रतादौ पूर्णिमा, गुरू पूर्णिमा, शु.रा. 10,12,1,4,5,8 अ.रा. 11,2,3,6,7,9 शुभांक- 3,5,9.

व्यापार भविष्य

आषाढ शुक्ल पूर्णिमा को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से मैथी धनियां, हल्दी, जीरा, आदि में तेजी होगी. सोना, चांदी, शेयर आदि में मोती, बिनौला, लोहा, में तेजी का रूख रहेगा. आज वायदा विचार में मंगल के बने भाव घटें, उसी में तेजी होगी. भाग्यांक 1599 है.

SUDOKU 7465

		5			8			
	7			3	5			
3						6		
							8	5
	6						1	
4	2							
		1						8
			7	4			3	
			2			7		

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक है. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है. आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 333 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें. ■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते. ■ पहेली का केवल एक ही हल है.

नवभारत सू-दोकू 7464

5	7	4	1	3	9	6	2	8
2	8	9	6	5	7	1	4	3
3	6	1	2	8	4	5	7	9
9	3	7	8	1	6	4	5	2
6	5	8	4	9	2	3	1	7
1	4	2	5	7	3	8	9	6
7	9	6	3	4	1	2	8	5
4	2	5	9	6	8	7	3	1
8	1	3	7	2	5	9	6	4